Registration No. RAJBIL /2016 / 69093

OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI

लघु उद्योग भारती

UDYOG TIMES

Volume -8 Issue-9 July - 2025

Total Pages - 40 Price - Rs. 10

New Understanding & New Vision for a New Journey

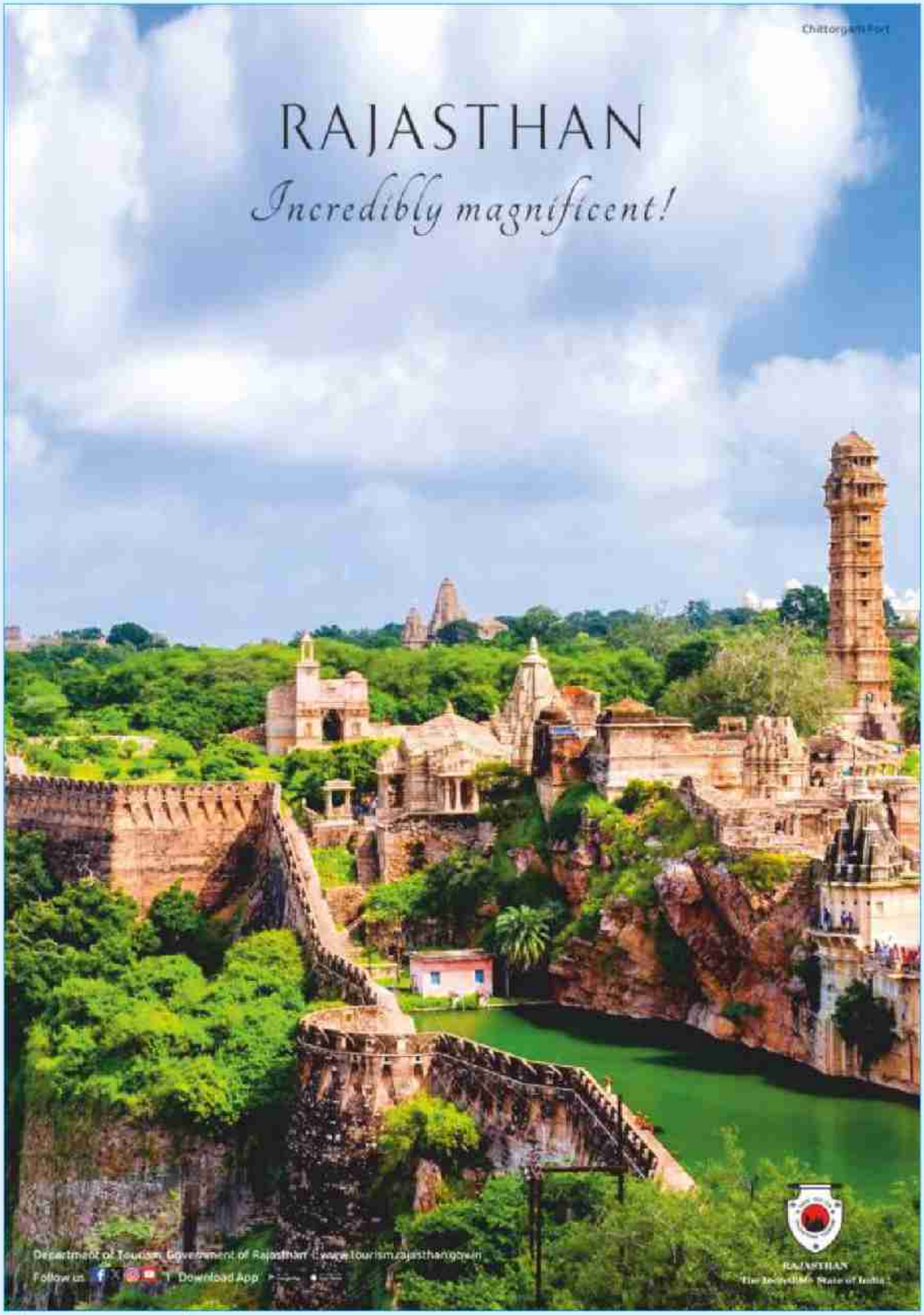
Chittorgarh Fort
RAJASTHAN
Incredibly magnificent!
Department of Tourism, Government of Rajasthan | www.tourism.rajasthan.gov.in
Follow us
Download App
RAJASTHAN

UDYOG TIMES

OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI

Volume -8 Issue - 9 July 2025

Editorial Board

■ *Patron*

Shri Ghanshyam Ojha, National President	098290-22896
Shri Prakash Chandra ji, National Org. Secretary	099299-93660
Shri Om Prakash Gupta, National Gen. Secretary	095602-55055

■ *Editor*

Dr. Kirti Kumar Jain	094141-90383

■ *Co-Editor*

Dr. Sanjay Mishra	098295-58069

विवरणिका

Editorial	03
भारत-ब्रिटेन संबंधों का नया दौर शुरू	05
Cyber Security	07
Intellectual Property	09
Quick Commerce in India	11
Long Awaited Issues	14
समावेशी विकास है प्राथमिकता	15
उद्योग, वन, पर्यावरण	18
ELI Scheme	21
LUB's NEWS in Brief	22

Price - 10/- *Life Membership 1000/-*

Corporate & Head Office :
Shri Vishwakarma Bhawan 48, Deen Dayal
Upadhyay Marg, Rouse Avenue, New Delhi-110002
Website : www.lubindia.com
Email : headoffice@lubindia.com
Ph.: 011-23238582
Registered Office :
Plot No. 184, Shivaji Nagar, Nagpur-440011
Ph.: 0712-2533552

India-UK Free Trade Agreement Let's Benefit from it...

Editorial

Dr. Kirti Kumar Jain
kkjain383@gmail.com

At a time when nations across the globe - just after Donald Trump took over the Presidency of the US - are caught in tariff war, India too is facing mounting threats of import tariffs from the United States. And the free trade agreement we signed with the UK recently offers a much-needed breather, especially for our MSME sector.

In fact, the FTA will provide significant market access to our MSMEs and give them a much-needed boost, especially to the labour-intensive sectors such as apparel, auto components, jewellery, and leather goods.

With the new FTA signed between the two nations, bilateral trade is expected to increase by an additional $32 billion annually by 2040, up from the current level of $52 billion. India is a major market for the UK and was its 11th largest trading partner last year. Under the signed agreement, exporters from the UK specially from sectors such as cosmetics, aerospace, machinery, soft drinks, and cars will benefit as they will face lower tariffs on exporting to India. On the other hand, 99 percent of all Indian exports to the UK will be duty free and with the UK opening its market, Indian exporters will have a level playing field and it will be a big win for them, especially for the MSMEs.

The official figures of India-UK trade, Indian exports to the UK accounts for approximately 4.15% of its total trade and stands at over $34 billion. Also in the current global trade environment, time was apt to forge new trade alliances and reduce over dependence on major economic powers like China and the US. SMEs must applaud our government whose relentless efforts took shape in the form of this India-UK FTA. They can look beyond our traditional trade partners and build new trade relationships for future economic growth and stability.

It is believed that this free trade agreement marks more than just a diplomatic milestone. It is without doubt a strategic move that aligns with India's long-term trade interests and I hope it serves as a blueprint for future trade agreements to come.

I want to know your opinion.

□□□

निरोगी राजस्थान

राजस्थान सरकार

हर रविवार 30 मिनट

मच्छरों पर वार

Check, Clean, Cover
STEPS TO DEFEAT DENGUE

हर रविवार सूखा दिवस मनाएं, स्वयं और परिवार को डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बचाएं

रविवार के खास कार्य

घर के कूलरों व पानी की टंकियों को रगड़कर साफ करें व सुखाने के उपरांत ही पुनः उपयोग में लायें। घर के आस-पास जहाँ कहीं भी रूका व ठहरा पानी हो उसे सुखा दें।

पानी की टंकियों के ढक्कन बंद रखे। सप्ताह में एक दिन इनको खाली करें व सुखाने के उपरांत ही उपयोग में लायें।

गमलों के नीचे रखे बर्तनों में से पानी को निरन्तर सुखायें।

घरों में कहीं भी पानी न जमा होने दें। पुराने टायर, बर्तनों आदि को हटा दें और यदि हटा न सकें तो उनमें जमा पानी को निकाल कर सुखा दें।

बचाव व नियंत्रण के उपाय अपनायें

दरवाजों व खिड़कियों पर जाली लगवायें।

पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें व मच्छरों से बचाव की क्रीम, स्प्रे या अगरबत्ती का उपयोग कर सकते हैं।

सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।

स्वास्थ्य केन्द्र ... मुफ्त

बचाव ही उपचार है

सर्दी व कम्पन के साथ बुखार जब आए,
तुरन्त जाकर खून की जांच कराएं।
हो सकता है यह मलेरिया का बुखार हो।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें टोल फ्री : 104/108

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, (आई.ई.सी.) राजस्थान, जयपुर

ऐतिहासिक व्यापार समझौते से भारत-ब्रिटेन संबंधों का नया दौर शुरू

99% भारतीय सामान को टैक्स मुक्त एंट्री एवं 2030 तक 10.25 लाख करोड़ ट्रेड लक्ष्य
ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इसे ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण समझौता बताया

भारत और यूनाइटेड किंगडम ने बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर 24 जुलाई को हस्ताक्षर किए। यह ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक व्यापार माहौल अस्थिर दिख रहा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पारस्परिक शुल्क लगाने की धमकियाँ दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) दोनों देशों के लिए "न केवल एक आर्थिक साझेदारी, बल्कि साझा समृद्धि की योजना" की शुरुआत है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री कीर स्टारमर के गृहनगर 'चेकर्स' में समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक दिन बताया क्योंकि "वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद, दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते को पूरा किया है।"

पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच 2030 तक ट्रेड को दोगुना कर सवा 10 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तीन साल से चल रही एफटीए की वार्ताओं के बाद भारत को बड़ी सफलता मिली है। भारत से निर्यात होने वाले 99% सामान को ब्रिटेन के बाजारों में टैक्स फ्री एंट्री मिलेगी। सबसे बड़ी राहत भारत के श्रम आधारित (लेबर इंटेंसिव) टेक्सटाइल, जेम्स–जूलरी के और लेदर गुड्स को मिलेगी। इस बीच, एफटीए के बाद श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता के नाम पर कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को ब्रिटेन ने पूरा सहयोग दिया है। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करेंगे।

किन सेक्टर्स को होगा फायदा-

कृषि सेक्टर- बासमती, अंगूर, मसाले, अल्फांसो, मछली जैसे उत्पादों का निर्यात सात हजार करोड़ रु. से 3 साल में दोगुना हो जाएगा।

टेक्सटाइल सेक्टर-

ब्रिटेन में भारतीय टेक्सटाइल पर 12 % टैक्स था जो अब जीरो हो गया। बांगलादेश, पाकिस्तान और कम्बोडिया के टेक्सटाइल उत्पादों पर ब्रिटेन में पहले से जीरो टैक्स है।

जेम्स-जूलरी सेक्टर-

अभी ब्रिटेन 4% शुल्क लगाता था। इसे फ्री करने पर 8100 करोड़ का ट्रेड पाँच साल में दोगुना होने की संभावना है।

फार्मा सेक्टर-

भारत अभी 5600 करोड़ रुपए का फार्मास्युटिकल उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात करता है। जीरो टैरिफ से फार्मा सेक्टर में तीन गुना तेजी आने की संभावना हैं।

केमिकल सेक्टर-

ब्रिटेन ने जीरो टैरिफ लगाया है। अगले तीन साल में केमिकल निर्यात बढ़कर 7300 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है।

सर्विस सेक्टर-

भारतीय फर्मों को 36 सर्विस क्षेत्रों में बिना 'इकोनॉमिक नीड्स टेस्ट के पहुंच मिलेगी। 400 भारतीय डॉक्टर्स को भी एंट्री।

एविएशन सेक्टर-

रॉल्स रायस होसुर (तमिलनाडु) में विस्तारित प्लांट लगाएगी। 5 साल में 5600 करोड़ के विमानों की सप्लाई हो सकेगी।

लेदर सेक्टर-

16% टैक्स था जो अब जीरो हुआ। दोसाल में ब्रिटेन को लेदर उत्पादों का निर्यात बढ़कर 7700 करोड़ रुपए होने की संभावना है।

प्लास्टिक सेक्टर- पहले 6%, टैक्स था जो अब जीरो हो गया है। 5 साल में 15% ग्रोथ के साथ 1600 करोड़ का निर्यात होगा। खिलौना इंडस्ट्री को भी बड़ा विस्तार मिलेगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद-

पहले 14% टैक्स था अब टैक्स फ्री है। ब्रिटेन में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की 5 साल में 15% बढ़ोतरी होगी।

ब्रिटेन से आयात- ब्रिटेन से भारत आने वाली जगुआर जैसी लग्जरी कारों पर आयात शुल्क 100% से घटाकर 10% होगा। टाटा ग्रुप की जगुआर, लैंड रोवर समेत रोल्स रॉयस और बेंटले कारें सस्ती होंगी। हालांकि, यह छूट सीमित कोटे के तहत दी जाएगी, यानी सभी कारों पर एक जैसी रियायत नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रिक–हाइब्रिड वाहनों के लिए भी नई संभावनाएं खुलेंगी। स्कॉच व्हिस्की पर 150% से घटकर 75% आयात शुल्क होगा। अगले 10 साल में इसे 40% तक लाया जाएगा। मशहूर ब्रिटिश स्कॉच व्हिस्की जॉनीवॉकर, चिवास रीगल सस्ती मिलेंगी। ब्रिटेन के सामानों जैसे कॉस्मेटिक सॉफ्ट ड्रिंक्स, कपड़े, जूते, गहने, चॉकलेट, बिस्किट और मेडिकल डिवाइस पर भी आयात शुल्क घटेगा। सभी ब्रिटिश प्रोडक्ट पर औसत टैरिफ 15% से घटाकर 3% किया गया है। □□□

Cyber Security in Generative AI Era

Risks and Opportunities for MSMEs

Tech Talk

Anil Pathak

Senior Director in Multinational Company.
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
Executive Council Member of Delhi Chapter
anil.pathak@ieee.org

Advancements in Generative AI technologies are evident, and this is no longer a future prediction. This is touching almost every sector, such as industry, healthcare, education, IT, and ITES. This also affects every organization irrespective of the size of companies, such as large enterprises or micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs). The impact is seen not only in professional domains, but also in personal lives, in terms of searching for information, analysing large documents, or creating innovative images. In all this, there is still a debate about which application is more impacted by Generative AI and whether jobs are created or lost. Overall, there is one field that would benefit significantly and create ample opportunities, that is, cybersecurity.

A Double- Edged Sword: Generative AI and Cyber Security

From a cybersecurity perspective, Generative AI is a double- edged sword. While it opens new fields of transformative defence capability, it also opens an unprecedented cyber threat. This enables attackers to have highly personalized phishing attacks but simultaneously enables the automatic detection of vulnerability. As saying goes, "With great power comes great responsibility', and hence with the added power of Generative AI, comes the added responsibility to ensure that the systems continue to be secure. This additional responsibility becomes more challenging for MSMEs, owing to their limited budgets and resources.

"The Rise of AI-Powered Cybercrime: India's Threat C Mitigation Report 2025". highlights that "In 2024 alone, India registered over 19.18 lakh cybercrime complaints, up from 15.56 lakh in 2023, reflecting a tenfold jump since 2019". Consequently, cyberattacks have increased with an increase in the

availability of Generative AI technology. While cyber attackers are sharpening their tools to attack, MSMEs also need to improve their cybersecurity defence mechanisms.

Real World Implications: Connected Eco System

Recently, during visit to IIT, Roorkee, research topics related to "Cybersecurity impacts on Electric Vehicles and the National Grid" discussed. With the help of vehicle-to-grid (V2G) technology, tomorrow's EVs would not only be drawing electricity from Nation's Grid but would also have the capability to give back electricity to the grid, as the need arises. This technology has evolved in India, and field trials have been conducted in the IIT Bombay. All this needs to be done in a very secure manner to avoid disaster- like situations due to cyberattacks on the nation's grid. As there has been tremendous growth in the Electric Vehicle sector and its connected ecosystem, the related cybersecurity domain provides additional opportunities to the MSME sector for growth.

Digital Transformation & Expanded Threat Surface

Owing to advancements in Industry 4.0 / 5.0, in terms of Internet of Things (IoT), Automation, Cloud, Digital Twin, 3D printing, etc., the government's push in digitalization is making people's lives relatively convenient, but this also increases the cybersecurity risk due to increased digital attack surfaces. A single data breach can cause losses in terms of confidential data, financial damage, and penalties as per the DPDP (The Digital Personal Data Protection) 2023 act.

Challenges & Opportunities for MSMEs

This phenomenon affects the MSME sector in several ways.

1. The MSME sector has a limited budget to ensure that cybersecurity is not compromised in pursuit of the latest technologies. In fact, it is essential to safeguard running businesses/operations before implementing these digitalization initiatives.
2. The MSME sector, especially in the tech field, can also cash in this opportunity to offer various consultancy, training, integration, audit, verification, and validation (PEN Test, etc.) to various other companies. This also opens opportunities for training, learning, and development.
3. Uttar Pradesh Govt. is coming up with AI City in Lucknow, and companies related to cyber securities can use this opportunity to open start-ups in each area.

Recommendations for MSMEs

In summary, Generative AI is here and MSMEs should not just react to cybersecurity impacts but plan to take advantage of it. This would require a mindset shift to avoid defending but innovate to remain relevant in the current scenario. Cybersecurity can be offered as a service along with secure digital practices in the new AI ecosystem. MSMEs also need to collaborate with institutions like IEEE (Instituteof Electrical and Electronics Engineers), IETE (The Institution of Electronics and Telecommunication Engineers), Cert In (Computer Emergency Response Team) and MeitY (The Ministry of Electronics and Information Technology) for better coordinated planning and response. A systematic response would decide the fate of MSME: flourish or perish!

□□□

ESIC has approved SPREE-2025

The Employees' State Insurance Corporation (ESIC) has approved SPREE-2025 (Scheme for Promotion of Registration of Employers and Employees) during its 196th Meeting held at Shimla (HP), under the chairmanship of Dr. Mansukh Mandaviya, Union Minister for Labour & Employment and Youth Affairs & Sports. It is a special initiative aimed at expanding social security coverage under the ESI Act. The scheme is active from 1st July to 31st December, 2025 and provides a one-time opportunity for unregistered employers and employees- including contractual and temporary workers - to enrol without facing inspections or demands for past dues.

Under SPREE-2025

i) Employers can register their units and employees digitally through the ESIC portal, Shram Suvidha and MCA portal.

ii) Registration will be considered valid from the date declared by the employer.

iii) No contribution or benefit will apply for periods prior to registration.

iv) No inspection or demand of past records will be made for the pre-registration period. It is requested to bring it to the notice of members of your association, so that benefit of the scheme is obtained by the units / factories/ employees who are yet to be registered under ESI Scheme.

□□□

Intellectual Property Makes Your Pie Bigger!

Safeguarding Innovation & Growth

Point of View

Rahul Dutta
Patent Attorney, Intellectual Property Lab
mail@iplab.in

Introduction-

The U.S. President, Donald Trump, has unilaterally abolished the harmonised low tariff system for international trade. He is the president of the U.S., but his decisions are causing repercussions in global trade. Why?

They aim to generate more revenue for their country at the expense of others around the world. The U.S. can pursue this goal because most of its revenue-generating assets are intangible.

The U.S. is the biggest economy in the world. Manufacturing makes up just 11% of the U.S. GDP, while the rest comes from the service sector. The IP-intensive industries make up about 40% of the UK's GDP.

We have observed the increasing influence of digital assets over the past twenty years. The item itself has become less important; the value now resides in what is embedded within a tangible product.

Both the pricing and selling probability of a shirt manufactured in Ludhiana are higher for shirts that carry a brand tag and a certification tag, such as 100% cotton.

We are living in an age of the Knowledge Economy, characterised by the development of monopoly-centric knowledge tools. It is a time of disruptive innovations. Twitter, a podcast application, was launched in 2006. By 2012, Twitter had gained 100 million users who were posting 340 million tweets daily. In a $44 billion deal, Twitter's ownership changed, and it became X in 2024.

We are one of the oldest civilisations with a strong foundation in science, technology, industry, and commerce. In addition to intellectual property, we possess a vast reservoir of traditional knowledge to bolster our economy.

Intellectual Property (IP) includes creations of the mind, such as inventions, trademarks, designs, and

artistic works. Protecting IP is vital for small and medium-sized enterprises (SMEs).

Protecting Innovations-

SMEs often led innovation with unique products and services. By protecting their intellectual property, they prevent competitors from copying or using their inventions without consent. This safeguard encourages continuous innovation and growth.

Securing Competitive Advantage-

Having exclusive rights to specific technologies or brand names provides SMEs with a competitive edge. This enables them to stand out in the market and maintain a unique identity, which can be essential for attracting customers and fostering trust and loyalty.

Increasing Business Value-

Intellectual property can greatly boost the value of an SME. Patents, trademarks, and copyrights are valuable

assets that can raise the company's worth, attract investors, and even be sold or licensed for profit.

Legal Protection-

Intellectual property laws offer legal protection to SMEs, enabling them to act against infringements. This legal framework assists businesses in safeguarding their innovations and ensures they can operate without the risk of losing their competitive advantages.

Encouraging Investment-

Investors are more inclined to back businesses with protected intellectual property. It shows that the company has valuable assets and is committed to innovation, making it a safer and more appealing investment.

Expanding Market Reach-

With secured intellectual property, SMEs can confidently expand into new markets. IP protection in various regions ensures that their products and services are safeguarded worldwide, opening-up international growth opportunities.

Building Brand Reputation-

Trademarks and copyrights assist SMEs in establishing and preserving their brand reputation. They ensure that consumers identify and trust the company's products and services, which is essential for long-term success.

Preventing Imitations-

By securing intellectual property rights, SMEs can prevent others from copying their products and services. This protection helps maintain their market position and prevents potential losses from counterfeit goods.

Facilitating Partnerships-

Protected intellectual property facilitates partnerships and collaborations for SMEs. It provides a clear framework for sharing and utilising innovations, fostering mutual growth and development.

Stimulating Industry Growth-

SMEs are vital to economic growth, making the protection of their intellectual property essential to sustain this contribution. IP protection encourages innovation, competition, and investment, all of which collectively promote economic development.

Conclusion-

Intellectual property is crucial for the success and growth of SMEs. It safeguards innovations, secures competitive advantages, enhances business value, and offers legal protection. By safeguarding their intellectual property, SMEs can boost their reputation, prevent imitations, and promote economic growth. In simple terms, IP is the key to unlocking the full potential of small and medium-sized enterprises, ensuring their innovation and success in the marketplace. The success of Micro and Small Enterprises (MSMEs) contributes 30% to India's GDP, supporting livelihoods at the grassroots level.

□□□

2nd Swayamsiddha Exhibition was conducted by Jhalawar Women Wing on 26-27 July, 2025.
Total 62 Women Entrepreneurs from Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh and
Rajasthan State Exhibited their Products.

Quick Commerce in India: Employment Shake-up and the Way Forward

"India's Economic Growth, Digital Economy, and Financial Architecture have the Potential to become a Major Economic Power in the coming decades."

New Wave

Churchil Jain
Member,
Laghu Udyog Bharati, Udaipur (Raj.)
churchil.jain294@gmail.com

The rise of Quick Commerce (Q-Commerce), delivering groceries and daily essentials within 10–15 minutes is reshaping the Indian retail landscape and transforming how urban India shops. Platforms like Zepto, Blinkit, Swiggy- Instamart, and BigBasket now have rapidly grown in metros, Tier-1 and Tier-2 cities. Promising unmatched speed, convenience, and efficiency.

The core idea behind Q-Commerce is simple: instant gratification. Consumers can now order a packet of milk, a toothbrush, or a kilo of tomatoes and expect it at their doorstep in under 10 to 15 minutes. This is made possible by tech-enabled dark stores, small and strategically located warehouses and a dense delivery network partners (also called Gig Workers) on two-wheelers.

As per a report published by RedSeer Consulting, the quick commerce industry is expected to reach a market size of $5.5 billion (Around INR 48000 crore) by 2025 and further to grow with a CAGR of 40%-45% in next 3 years.

"Speed is the new loyalty". But behind this fast-paced revolution lies a complex web of economic, employment, and societal impacts. Change is never simple, especially when one goes beyond the first-order effects. But change is highly needed in an economy to accelerate its growth.

When the concept of supermarkets first came in India it was assumed that it would impact badly to small kirana stores and the vegetable stores. But years of co-existence shows the importance of both supermarkets and kirana stores, and nothing happened as bad as it was presumed. Though, weather the same thing will result after this quick commerce revolution is what the time will tell in years to come.

Let's have a look at the both sides of this new coin; As per a 2022 report by NITI Aayog, Q-commerce platforms in India employ over 2.5 lakh gig workers. They employ around 62 to 64 people per INR 1 crore of monthly gross merchandise value (GMV) or the gross sale over their platform. As per Aayog's estimates the gig workforce expected to expand to 2.35 crore workers by 2029-30. It is becoming fastest job provider among Tier 1 and Tier 2 cities. Many youths, college

students, and unemployed individuals have found flexible earning opportunities with companies like Blinkit and Zepto.

Average income ranges from ₹18,000 to ₹25,000 per month for full-time riders, depending on city and number of orders. With surge incentives, some delivery partners earn up to ₹30,000/month, especially during festivals or promotions. For households' perspective, it is highly convenient for time starved urban consumers. Emergency Medicines, Baby products and last-minute need handled quickly. It is an easier access for women and elderly to get essentials without going out.

It also helps in advancement of tech products such as innovation in logistics, AI routing and store optimization. As they say energy transform from one form to other, same applies here with businesses also. Many local grocery/kirana stores are witnessing a drop in footfall, especially in high-income urban neighborhoods. However, some kiranas are adapting by joining digital platforms like JioMart Partner, Amazon Easy, or Udaan to stay competitive. Still, the pressure of matching prices and convenience is tough for standalone kirana stores. But in times to come they will learn to co-exist with. "We must digitize and adapt to stay relevant," says Shri Nitin Jain, a retailer in Udaipur who now delivers via WhatsApp and Swiggy Genie.

Supermarkets face competition too, not just in price but in speed. Big retail chains like Reliance Fresh, Jio Mart and DMart have felt the pinch of Q-Commerce growth. In response, chains like DMart have started their own express delivery model DMart Ready to retain market share. Same is with Jio Mart Hyper in which they have started delivering within 30 Minutes. Retail chains are being forced to invest in digital infrastructure, warehouses, and last-mile delivery.

Then comes the social dimension. Many people on social media wrote about the loss of neighborhood Kirana stores that may have supplied to their family for generations. It is only apt to remember that human connections that go beyond family and friends. The kirana store owner who knew what kind of vegetables or brand of milk your family liked, also contribute to well-being and longevity. This loss is not economic, but human.

Then there is a massive impact on construction industry per say. Shri Bhavesh Chhaparwal owner of a real estate project management consulting company says that the construction industry facing a huge problem in getting labors for their daily construction work. As the average per day wage for a labour in a tier 1 and 2 cities is around INR 500 to 600 per day and demands heavy physical work for 6 to 8 hours per day. In the same time with no such hard work the same young labour can earn more money by becoming delivery boy or agent.

In a discussion with senior Architect Shri Sunil Ladha, he emphasized on the need of adoption and use of 3D printing in construction where by using Machines a wall can be made faster, perfect in shape and cost effective. So that construction industry can come up with labor shortage problem.

Quick commerce in India is here to stay, driven by convenience-loving consumers and tech-driven platforms. However, balancing growth with ethics is the need of the hour. Companies must ensure fair working conditions, eco-friendly practices, and collaboration with small retailers to make Q-Commerce a sustainable part of

India's retail future.

Prof. R. Nagaraj, economist, Indira Gandhi Institute of Development Research warns "We are building convenience for the rich, but must also build fairness for the workers."

As the sector grows, the challenge will be not just delivering fast-but doing it responsibly. **Laghu Udyog Bharati** here would like to demand a few things from government for the betterment of this new age business model.

Firstly, Gig workers or the delivery agents are not considered as full-time employees of these Q Commerce platforms, hence they are not entitled for PF or Insurance benefits. However, GoI in its union budget 2025-26 mentioned the provision for registration of gig workers on Eshram portal and providing Aushman Arogya Insurance Coverage but it has not been implemented properly on ground yet.

Second, as under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, union government's Ministry of Finance launched PM SVANidhi Scheme for street vendors in year 2019 by which for the first time unorganized street vendors were able to get loans from public sector banks. Such a Scheme should be made available for Gig workers also so that they can have financing facilities for their betterment.

And last, A Government platform for small business owners to get partnering with quick commerce companies is need of the hour. Through which all small business owner can be partnered with these quick commerce companies to sell their products.

Quick commerce has certainly revolutionized urban shopping in India. As country races ahead with Quick Commerce, the real test will be not just how fast it delivers but how fair and inclusive that journey is.

□□□

छत्तीसगढ़ प्रांत की कार्यकारिणी का किया पुनर्गठन

लघु उद्योग भारती छत्तीसगढ़ ने वार्षिक बैठक के साथ उद्यमी सम्मलेन का आयोजन अखिल भारतीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी, उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, वित्त मंत्री श्री ओमप्रकाश चौधरी, सीएसआईडीएस के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल की विशेष उपस्थिति में किया। संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी ने उद्यमियों को भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया कि जब देश के छोटे से छोटे गांव भी आत्मनिर्भर हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि हमारे देश को पुनः उसी गौरव तक पहुँचाना उद्यमियों के ही हाथ में है। अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष श्री समीर मूंदड़ा ने नयी कार्यकारिणी की घोषणा की। प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती (डॉ.) सीपी दुबे, उपाध्यक्ष श्री दीपक उपाध्याय, महामंत्री श्री कैलाश चंद्रवंशी, कोषाध्यक्ष श्री अनिल बाकलीवाल, सचिव श्री जितेन्द्र चंद्राकर, श्रीमती तूलिका पांडेय एवं श्री प्रांजल ठाकुर को मनोनीत किया गया। कार्यक्रम में 250 उद्यमी उपस्थित हुए एवं कुल 22 में से 18 इकाइयों ने अपना वृत्त प्रस्तुत किया।

LUB's Delegation met Union Health Minister for Long Awaited Issues of Pharma & Textile Industry

LUB's delegation led by National President Shri Ghanshyam Ojha and General Secretary Shri Om Prakash Gupta met Union Health Minister Shri JP Nadda for pending issues at New Delhi on 17th July.

Key agenda points discussed for Pharma Sector-

1. Future of MSME Pharma Companies below 50 Cr. Turnover: Protection for companies with turnover below ₹50 crores and extension of Revised Schedule-M to prevent closures.
2. Sample Fail Issues: Concerns about good quality products (97.3%) not being appreciated, while 2.64% NSQ products are targeted through risk-based inspections and closures.
3. International Market Impact: Alerts in African markets based on NSQ issues in India and the impact on "Brand Bharat."
4. USFDA Recalls: Impact on "Brand Bharat" due to USFDA recalls.
5. Representation in DTAB: Acceptance of LUB representative appointment in DTAB.
6. Drug Tribunal Board: Formation of the board following Section 33P guidelines and the Jan Vishwas Bill.
7. Export NOC Hurdles: Removal of hurdles for exports to 183 countries, discussed in length and instructed authorities to look after immediately.
8. NDCT Rules 2019: Implementation should not be retrospective, safeguarding approvals for sustained-release formulations manufactured before 2019.
9. Guidance Module: Need for guidance on API, excipients, and solvents industry for import and domestic manufacturing.
10. SQA matters and import hurdles about certain chemicals.
11. Foscos/ Fssai related issues and Nomination of Lub Representatives, which he accepted.
12. PLI scheme and Lub members investment and still grant is pending for disbursement,
13. Formation of Indian Advisory Forum as per 2017.

Key agenda points discussed for Textile Sector-

1. Reconsidering QCO on PTA POY FDY in textile industry.
2. After the implementation of QCO on yarn, the import of yarn in the country has reduced effectively but the import of cloth has increased which is not good for MSME textile industries.
3. Demand to impose QCO on cloth also to increase the import of cloth. it will destroy the downstream MMF textile industry and modernization process through various versions of TUFS.
4. In the last few years, there has been huge investment in knitting and weaving industry but implementation of QC on MMF yarn has resulted in huge import of readymade garments which ultimately affects the concept of Make in India as well as the idea of Aatmanirbhar Bharat.
5. To Review the QCO on MMF yarn like Polyester POY FDY and its impact on downstream industry.
6. To provide certain quantitative relaxations in import of non-BIS polyester POY and FDY for consumption in production of downstream articles for sale in domestic market of India and implement QC on readymade garments and apparel.

The Minister will call for final Resolutions in the coming days and requested to LUB's President and General Secretary to join various Delhi based meetings as a special invitee to explain ground realties of MSME industries.

On this occasion, National Head Pharma Sector Dr. Rajesh Gupta, Maharashtra Pharma Wing Head Dr. Ravleen Khurana, Madhya Pradesh Pharma Wing Head Shri Amit Chawla, importer in chemical and textiles industries Shri Ravi Poddar and National Head Textile Sector Shri Mahesh Hurkat were present.

□□□

अंत्योदय, सुशासन और समावेशी विकास है प्राथमिकता

आपणो अग्रणी राजस्थान

राजस्थान विशेष

उद्योग टाइम्स डेस्क

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने एचसीएम रीपा में आयोजित राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आरंभ किए गए 'आशान्वित जिला' और 'आशान्वित ब्लॉक' कार्यक्रमों ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ। भीमराव अंबेडकर के अंत्योदय के विचारों से प्रेरित है, जिनके माध्यम से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि नीति आयोग द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन और आधारभूत संरचना जैसे छह प्रमुख संकेतकों के आधार पर चयनित जिलों और ब्लॉकों में समग्र विकास के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान के बारां, जैसलमेर, धौलपुर, करौली और सिरोही जिलों के साथ 2023 में 27 ब्लॉकों को भी इस योजना में सम्मिलित किया गया जिन्होंने उत्कृष्ट प्रगति की है और इससे सुशासन और समावेशी विकास को नई गति मिली है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नीति आयोग द्वारा निर्धारित छह प्रमुख संकेतकों की पूर्ण संतृप्ति प्राप्त करने वाले जिलों और ब्लॉकों को सम्मानित किया। करौली जिले को स्वर्ण पदक से, जबकि बारां, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही को कांस्य पदक से नवाजा गया। वहीं, जायल (नागौर), रानी (पाली) और खैरवाड़ा (उदयपुर) ब्लॉक को स्वर्ण पदक प्रदान किए

गए। साथ ही 23 अन्य ब्लॉकों को रजत, कांस्य एवं ताम्र श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया।

मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि 'गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना' के अंतर्गत 41 ब्लॉकों में नवाचार और बहुआयामी विकास के माध्यम से उन्हें विकसित ब्लॉकों की श्रेणी में लाने का प्रयास जारी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 'विकसित राजस्थान 2047' विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, जिसमें भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालीन योजनाएं सम्मिलित की जा रही हैं।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मुख्यमंत्री ने 'हरियालो राजस्थान' अभियान का उल्लेख किया, जो प्रधानमंत्री के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से प्रेरित है। उन्होंने बताया कि हरियाली तीज के अवसर पर राज्यभर में ढाई करोड़ पौधारोपण कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया है, और वर्ष 2025 के लिए 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कार्यक्रम में नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव श्री रोहित कुमार, मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, एचसीएम रीपा की

महानिदेशक श्रीमती श्रेया गुहा, आयोजना विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री भवानी सिंह देथा सहित चयनित जिलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

आईटी क्षेत्र में राजस्थान की ऐतिहासिक पहल

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में राजस्थान प्रदेश ऐतिहासिक परिवर्तन की ओर अग्रसर है। सरकार द्वारा उठाए जा रहे बहुआयामी कदमों ने राजस्थान को तकनीकी विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। राज्य सरकार का उद्देश्य है– आधुनिक तकनीकों का लाभ आमजन तक पहुँचाना, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और राजस्थान को क्रिएटिव टेक्नोलॉजी हब बनाना।

मुख्यमंत्री श्री शर्मा के मार्गदर्शन में तैयार की गई राजस्थान एआई पॉलिसी 2025 न केवल जवाबदेह और नैतिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देगी, बल्कि राज्य में स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी गति देगी। इसके तहत एक विशेष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई (CoE-AI) की स्थापना की जाएगी, जो स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करेगा।

इसी प्रकार, राज्य सरकार की एवीजीसी–एक्सआर पॉलिसी एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स और एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में रोजगार और निवेश के नए द्वार खोल रही है। सरकार ने रू.1000 करोड़ की लागत से चार अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलेरेटर्स स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा है, जिससे इनोवेशन और उद्यमिता को बल मिलेगा।

राजस्थान में डेटा सेंटर पॉलिसी–2025 के माध्यम से निजी क्षेत्र को डेटा सेंटर स्थापना हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य को विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम के रूप में विकसित करना है, जो सुरक्षा, विश्वसनीयता और दक्षता सुनिश्चित करेगा।

राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए कई प्रमुख उद्यमियों से एमओयू (MoU) किए हैं, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। इसके अतिरिक्त, जयपुर और जोधपुर में स्थित भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर (RSDC) देश का सबसे बड़ा सरकारी डेटा सेंटर है, जो 99.995% अपटाइम की गारंटी के साथ अत्याधुनिक सेवाएं प्रदान करता है।

इन पहलों के माध्यम से राज्य सरकार नवाचार, पारदर्शिता और डिजिटल दक्षता को बढ़ावा दे रही है। डिजिटल राजस्थान की कल्पना को साकार करने की दिशा में यह एक ठोस कदम है, जो आमजन की सुविधा के साथ–साथ राज्य को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर एक तकनीकी नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करेगा।

दिल्ली प्रवास में राज्य के विकास पर चर्चा

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से कृषि भवन में प्रदेश में ग्रामीण विकास, कृषि क्षेत्र, लखपति दीदी योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सहित विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान श्री शर्मा ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से राजस्थान को इस वित्तीय वर्ष में मनरेगा योजना के तहत 4384 करोड़ रुपये जारी करने पर केन्द्रीय मंत्री का आभार जताया।

मुख्यमंत्री ने श्री चौहान से राजस्थान में केन्द्रीय सहयोग से ग्राम पंचायत स्तर पर 'कृषि पर्यवेक्षकों' की व्यवस्था करने, राज्य की बेहतर मूंगफली किस्मों के प्रोत्साहन हेतु अधिसूचित करने एवं राज्य में उत्पादित होने वाले अरंडी के

तेल के संवर्धन के लिए आग्रह किया। उन्होंने श्री चौहान को 'पर ड्रॉप–मोर क्रॉप', डिग्गी निर्माण और खेतों में तारबंदी से संबंधित योजनाओं के साथ ही जयपुर के बस्सी में कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की भी जानकारी दी।

मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान में बहुत शानदार कार्य हुआ है। केन्द्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने इस पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि प्रस्तावित आवासों के सर्वे के सत्यापन का कार्य पूरा होते ही अतिरिक्त मकानों के निर्माण की स्वीकृति दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पीएम–जनधन योजना के तहत भी आवासों का निर्माण करवाया जाएगा और कुल 7.46 लाख मकान बनाए जाएंगे। बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषि सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी, केन्द्रीय ग्रामीण विकास सचिव श्री शैलेश सिंह, आईसीएआर के महानिदेशक डॉ। एम.एल। जाट सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल से ऊर्जा एवं आधारभूत संरचना पर चर्चा

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने संसद भवन में केन्द्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल से भेंट कर राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में नवीन संभावनाओं, आवासीय परियोजनाओं एवं शहरी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से अंतरराज्यीय प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं नवीकरणीय ऊर्जा की अतिरिक्त प्रसारण क्षमता के उपयोग हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना निर्माण के लिए केन्द्रीय सहयोग का आग्रह किया। मुख्यमंत्री शर्मा ने केन्द्रीय मंत्री से जयपुर के मेट्रो फेज–2 एवं ई–बस सेवा के त्वरित क्रियान्वयन के लिए भी केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया।

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल से शिष्टाचार भेंट

मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर

पाटिल से राजस्थान में जल जीवन मिशन तथा राम जल सेतु लिंक परियोजना की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि इनसे राज्य में सिंचाई और पीने के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने श्री पाटिल को बताया कि इस मानसून में राजस्थान में अच्छी बारिश होने से प्रदेश के जलाशय समय पूर्व भर चुके हैं तथा कर्मभूमि से मातृभूमि एवं वंदे गंगा जल संरक्षण–जन अभियान के माध्यम से राज्य के भूजल स्तर में भी वृद्धि होगी। □□□

यमुना नगर में महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा

लघु उद्योग भारती हरियाणा के जिला यमुनानगर के जगाधरी में 14 जुलाई को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई जिसमें विद्युत निगम द्वारा बढ़ाए गए फिक्स चार्ज, नॉन कन्फॉर्मिंग इण्डस्ट्रियल एरिया को नियमित करने व आटा मिल के समक्ष आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अरविंद धूमल, HERC सदस्य श्री मुकेश गर्ग, स्थानीय विधायक श्री घनश्याम अरोड़ा, प्रदेशाध्यक्ष श्री शुभ आदेश मित्तल, अंबाला के जिलाध्यक्ष श्री विनोद बंसल और श्री प्रदीप गोयल सहित अन्य पदाधिकारी गण मौजूद रहे।

उद्योग, वन, पर्यावरण और खान विभाग विषयक राज्य स्तरीय संगोष्ठी

उद्योगों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए ज्वाइंट ग्रुप की घोषणा

लघु उद्योग भारती, राजस्थान ने उद्योग, वन, पर्यावरण और खान विभाग विषयक राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 9 जुलाई को किया जिसमें पहली बार एक मंच पर इन सभी विषयों में संवाद स्थापित करने का ऐतिहासिक प्रयास किया गया।

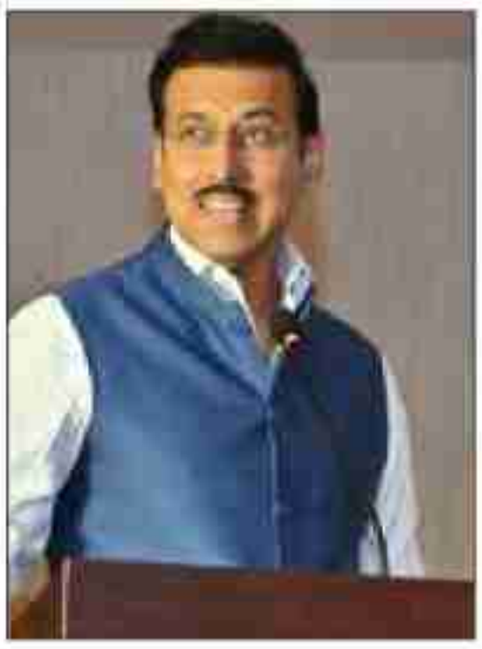

प्रदेश में व्यापार को आसान और सस्ता बनाने पर सरकार का फोकस

राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राज्य में व्यापार को सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि नई तकनीक, स्किल डेवलेपमेंट और मार्केटिंग के साथ क्वालिटी प्रोडक्ट ही उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में बनाए रख सकते हैं।

इस संगोष्ठी में उद्योग मंत्री श्री राठौड़ ने महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य में उद्योगों से जुड़ी समस्याओं के त्वरित और स्थाई समाधान हेतु एक ज्वाइंट ग्रुप गठित किया जाएगा, जिसमें उद्योग, वन, खान, स्किल डेवलपमेंट विभाग के साथ–साथ लघु उद्योग भारती जैसे अग्रणी संगठन को भी सम्मिलित किया जाएगा। यह समूह सभी विभागों के साथ समन्वय के साथ जमीनी समस्याओं को

चिन्हित करेगा और उनके सहज समाधानों के साथ इस ग्राउंड रिपोर्ट को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

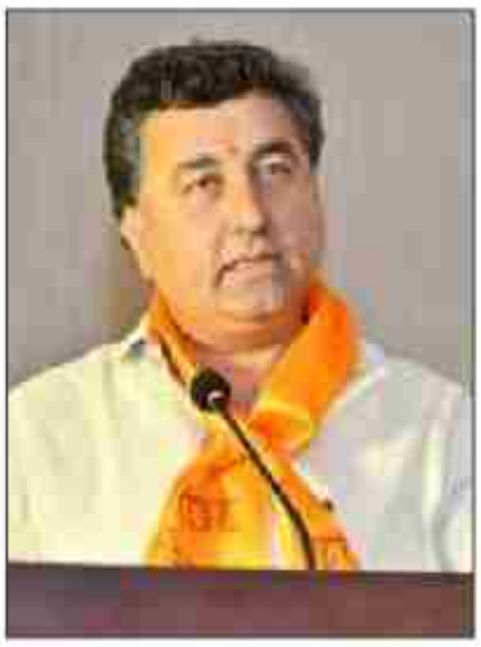

GST दर वृद्धि को रोके जाने की बड़ी उपलब्धि

इस अवसर पर उद्योग राज्य मंत्री श्री केके विश्नोई ने बताया कि जीएसटी काउंसिल में पत्थर पर टैक्स को 18% से बढ़ाकर 28% करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे उनके सतत प्रयासों से रोका गया। यह पत्थर उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी राहत है और सरकार की व्यावसायिक संवेदनशीलता का प्रमाण है। श्री विश्नोई ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों

में मार्बल–ग्रेनाइट पर जीएसटी दर और कम करने की दिशा में प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पुराने और अप्रासंगिक कानूनों और नियमों की समीक्षा कर उनमें आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे जिससे उद्योगों को वास्तविक राहत मिल सके।

राज्य में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण

प्रदेश के इंडस्ट्री कमिश्नर श्री रोहित गुप्ता ने कहा कि राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपयों के एमओयू में से चार लाख करोड़ से अधिक के निवेश को लगातार मॉनिटरिंग से धरातल पर लाया जा रहा है जो इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल बन रहा है। उन्होंने एमएसएमई, ओडीओपी और रिप्स आदि योजनाओं के बारे में जानकारी दी और प्रदेश को सौर ऊर्जा का हब बताया।

राजस्थान को विकासशील से विकसित प्रदेश बनाने के लिए भजनलाल सरकार प्रतिबद्ध

लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा ने कहा कि राजस्थान को विकासशील से विकसित प्रदेश बनाने के लिए भजनलाल सरकार प्रतिबद्ध है और इसमें संगठन की भूमिका सकारात्मक रहेगी। उन्होंने लघु उद्योग भारती को जोधपुर में आयोजित होने वाले हस्तशिल्प महोत्सव में अगले 4 वर्ष के लिए नोडल एजेंसी और इंडिया स्टोन मार्ट–2026 में सह आयोजक बनाने के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया। उन्होंने राइजिंग राजस्थान के सफल आयोजन के बाद सिंगल विंडो सिस्टम और रीको से उद्यमियों को जमीन के सीधे अलॉटमेंट के लिए भी राज्य सरकार की तारीफ की। श्री ओझा ने बताया कि संगठन सरकार के साथ 10 जिलों में स्किल डेवलपमेंट पर कार्य कर स्किल्ड लेबर उद्योगों के लिए तैयार कर रहा है।

एलयूबी की ऐतिहासिक पहल

लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय सचिव श्री नरेश पारीक ने बताया कि पहली बार इस संगोष्ठी में वन, पर्यावरण और खान विभाग एक मंच पर साथ आये जिससे इन विभागों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रदेश के उद्यमियों की व्यावहारिक समस्याओं और उनके समाधान पर खुला संवाद किया। उन्होंने भविष्य में भी इस तरह के विशेष संवाद सत्रों को आयोजित करने पर बल दिया।

राजस्थान की खनिज नीति देश में सर्वश्रेष्ठ, फिर भी कुछ व्यावहारिक जटिलताएँ

इस संवाद कार्यक्रम में प्रतिभागी उद्यमियों का कहना था कि राजस्थान की खनिज नीति को देश में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किंतु, इसके क्रियान्वयन में सामने आ रही चुनौतियाँ जैसे कि वन मंजूरी, पर्यावरणीय क्लीयरेंस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रक्रिया और खनन में खासतौर पर ड्रोन द्वारा वोल्यूमेट्रिक अस्सेस्मेंट और डिमार्केशन को संगोष्ठी में गहराई से चर्चा का विषय बनाया गया। पर्यावरण और खनन से जुड़े जटिल विषयों पर श्री सुदर्शन शर्मा, उपवन संरक्षक, एफसीए, मुख्यालय, जयपुर, श्री विष्णुदत्त पुरोहित, चीफ एनवायर्नमेंटल इंजीनियर, आरएसपीसीबी, जयपुर, श्री विजय शर्मा, सीनियर एनवायर्नमेंटल इंजीनियर, जयपुर, श्री दीपक तंवर, डायरेक्टर, खान विभाग, राजस्थान, श्री प्रताप मीणा वरिष्ठ खान अभियंता एवं श्री आलोक जैन अतिरिक्त निदेशक, भूविज्ञान ने स्पष्टता से जवाब दिए और सहयोग के लिए आश्वस्त किया।

इंडिया स्टोन मार्ट–2026 में 55% बुकिंग

कार्यक्रम में इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के संयोजक श्री नटवरलाल अजमेरा ने स्वागत भाषण में बताया कि विदेशों में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी और देशभर में रोड शो और कांफ्रेंस आदि के आयोजन से अब तक 55% बुकिंग हो चुकी है, जो पूर्व

आयोजनों की तुलना में अब तक की सबसे तेज और उत्साहजनक बुकिंग है। इससे यह स्पष्ट है कि राजस्थान प्रदेश पत्थर उद्योग को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार है!

लघु उद्योग भारती के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री शांतिलाल बालड़ ने सत्र को मॉडरेट किया। प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेंद्र शर्मा ने आभार व्यक्त किया एवं संचालन पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सीए योगेश गौतम और प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर सीडोस के वाइस प्रेसिडेंट श्री राकेश गुप्ता, एलयूबी प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मुकेश अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री श्री सुधीर कुमार गर्ग एवं जयपुर प्रांत अध्यक्ष श्री महेंद्र मिश्रा सहित बड़ी संख्या में उद्यमीगण उपस्थित रहे। अतिथियों ने भिवाड़ी में 19–21 सितम्बर को आयोजित आईआईएफ – 2025 का पोस्टर भी रिलीज किया।

□□□

स्वयंसिद्धा संकल्प सूत्र प्रदर्शनी इंदौर में संपन्न

एलयूबी मध्यप्रदेश की इंदौर महिला इकाई ने एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से 24 से 27 जुलाई तक स्वयंसिद्धा संकल्प सूत्र प्रदर्शनी आयोजित की जिसमें 60 महिला उद्यमियों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किये। इकाई अध्यक्ष श्रीमती वर्षा जैन ने बताया कि उद्घाटन सत्र में पूर्व लोकसभा स्पीकर श्रीमती सुमित्रा महाजन, एलयूबी प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश मिश्रा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मालवा प्रान्त की महिला कार्य प्रमुख श्रीमती माला ठाकुर ने उत्पादों का अवलोकन कर महिलाओं का उत्साह बढ़ाया। 25 जुलाई को महिला उद्यमी– सपनों से सृजन विषयका पैनल डिस्कशन में प्रदेश के एमएसएमई मंत्री श्री चैतन्य कश्यप और सफल महिला उद्यमियों को भी आमंत्रित किया गया जिन्होंने अपनी प्रेरक यात्रा को साझा किया।

26 जुलाई को उद्यमी निर्माण कार्यक्रम में 300 से ज्यादा युवाओं ने भागीदारी की जो अपनी पढ़ाई के बाद उद्यमी बनना चाहते थे। समापन–सत्र में प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र प्रदान किये। प्रदर्शनी में 15 हजार से अधिक लोगों ने विजिट की।

ELI Scheme to Generate More than 3.5 Crore Jobs in Two Years

Union Cabinet has approved Employment Linked Incentive (ELI) Scheme to generate more than 3.5 crore jobs in two years with an outlay of Rs.1 lakh crore focusing on manufacturing sector. The ELI scheme was announced in the Union Budget 2024-25 as part of the PM's package of 5 schemes for employment and skilling, with a total budget outlay of ₹2 lakh lakh crore for education, employment, and skills for 4.1 crore youth. The schemes aim to support first-time employment, job creation in manufacturing, employer support, skilling, and internships:

1. Scheme-A: First-Time Employment Support

Objective: Encourage first-time employment and support new entrants in the workforce

Benefits:

- First-time employees registered in the EPFO will receive a one-month salary of up to ₹15,000.
- Payment will be made in two instalments to ensure continuous support.
- This scheme aims to ease the transition into the workforce and provide financial stability during the initial phase of employment.

2. Scheme-B: Job Creation in Manufacturing

Objective: Boost job creation in the manufacturing sector and encourage employers to hire new employees

Benefits:

- Incentives will be provided directly to both employees and employers based on their EPFO contributions.
- Incentives will be scaled according to the number of years of employment, with a focus on the first four years.

This scheme aims to stimulate job growth in the manufacturing sector and support employers in expanding their workforce.

3. Scheme-C: Employer Support and Employment Generation

Objective: Encourage employers to hire additional employees and support employment generation

Benefits:

- The government will reimburse up to ₹3,000 per month for two years towards EPFO contributions made by employers for each additional employee hired.
- This scheme aims to reduce the financial burden on employers and incentivize them to create new job opportunities.

4. Centrally Sponsored Skilling Scheme

Objective: Enhance skills and employability of youth across the country

Benefits:

- 20 lakh youth will be skilled over five years.
- 1,000 ITIs will be upgraded in a hub-and-spoke arrangement to improve infrastructure and training facilities.

5. Internship Scheme in Top Companies

Objective: Provide valuable work experience and exposure to top companies for youth

Benefits:

- 1 crore youth will be placed in internships in 500 top companies over five years.
- Internships will be designed to provide hands-on experience and skill development opportunities.
- This scheme aims to enhance employability and prepare youth for the workforce.

□□□

IIT Ropar and LUB Signed MoU for Defence & Aerospace Sector

A landmark MoU was signed between IIT Ropar and Laghu Udyog Bharati (LUB), establishing a robust partnership aimed at empowering Indian MSMEs-particularly in the Defence & Aerospace sectors on 31st July.

Key initiatives under collaboration include:

- Sector-specific training through the Laghu Udyog Bharati Skill Development Center-Sohan Singh Smriti Kaushal Vikas Kendra, Jaipur.
- Innovation, prototyping, and technology development via IIT Ropar's state-of-the-art labs.
- Enhanced industry-academia exchange and policy advocacy.
- Enabling MSMEs to enter the technology-driven supply chain.

The MoU was formalized at IIT Ropar in the esteemed presence of delegates from both institutions. Laghu Udyog Bharati was represented by All India General Secretary Shri Om Prakash Gupta, All India Secretary Smt. Anju Bajaj, National Coordinator-Net Zero and Industry-Academia Smt. Jayanti Goela, All India Vice President Shri Arvind Dhumal, and Punjab State President Shri Pardeep Mongia along with other office bearers from Punjab and Delhi teams.

LUB extends their heartfelt gratitude to Director IIT Ropar Prof. Rajeev Ahuja and Director, DRIF (Defence Research & Innovation Foundation) Dr. Atharva Poundarik along with other esteemed members of the DRIF team and IIT Ropar faculty for this collaboration.

As part of the program, LUB representatives also visited the Central Research Facility of IIT Ropar, an experience that was both insightful and inspiring. This MoU is a step forward in building a future-ready MSME ecosystem through innovation, collaboration, and shared commitment to national development.

□□□

AP State Unit conducts AGM to Form New Executive

LUB's Andhra Pradesh State Unit conducted AGM at Guntur in the presence of LUB's National Organising Secretary Shri Prakash Chandra ji and Shri Madala Venkateswara Rao. The President welcomed the members followed by the annual report by General Secretary and Treasurer. The new executive committee of state for the year 2025-27 was announced. Shri Yogish Chandra President, Shri Ramesh Atluri General Secretary, Shri Dharaneesh Treasurer and 14 members are the part of new team. NWC members Shri Ananth and Shri A. Krishna Balaji addressed the members.

New Team Formed for Karnataka

LUB's Karnataka state formed the new team in the presence of Shri Prakash Chandra ji and Shri Mohan Sundaram. New office bearers for 2025-27 are as

mentioned- Shri Narayana Prasanna President, Shri Ravikumar General Secretary and Shri Lakshmisha Treasurer.

3rd Edition of Gramashilpi Mela held at Hubballi

The 3rd Edition of Gramashilpi Mela, the flagship event of Laghu Udyog Bharati-Karnataka and IMS Foundation was inaugurated by Smt. Jyothi Patil, Mayor Hubli-Dharwad City Corporation at Hubballi on 17th July. This 7-day Rural Artisans Mela features

more than 50 master artisans from Karnataka and neighbouring states, presenting a diverse range of products that highlight the rich traditional heritage and cultural excellence of India. The event is support by DC (Handicrafts), Govt. of India.

Installation Ceremony held for Greater Chennai Region

LUB's Tamil Nadu State Unit conducted Installation Ceremony for Four Districts of Chennai Region- Chennai, Thiruvallur, Kanchipuram & Chengalpattu at Ambattur on 12th July. The program commenced with a traditional prayer by National Vice President Shri Hariharan. State GS Shri Kalyan Sundaram warmly greeted the gathering with his insightful address.

Officials from SIDBI and Sundaram Finance actively participated and explained various developmental schemes available for MSMEs.

Welcome Address by State President VSV Ver. Chezhian and Motivational Talk was delivered by National EC Member Shri M.S. Vijayaraghavan. State Joint GS Shri Jayendran spoke on Entrepreneurial Ego. State IPP Shri M. Sivakumar emphasized the six key pillars driving organisational growth. State GS Shri Kalyanasundaram emphasized the importance of unity and disciplined growth aligned with national LUB goals.

NSIC Branch Opens @ Siliguri

NSIC's has opened a new branch at Siliguri on 17th July.

This branch will support LUB members manufacturing handicrafts and handloom to get free onboarding on ONDC platform and a hand holding for registration. On this occasion, All India National Secretary & In-charge West Bengal & Sikkim Shri Pravin Agarwal delivered a speech on Swavalambi Bharat Abhiyan and entreprenurship.

Pharma Wing met DCGI

LUB's Pharma Wing met with Drug Controller General of India Dr. Rajeev Raghuvanshi for long awaited issues on 20th July. The DCGI was agreed on few decisions on preliminary ground which are given as follows:

1) Reformation of Indian Drug Advisory Forum for quarterly basis with all leading association representatives for deliberations with Health Secretary, DCGI, Jt. DCGI and with CDSCO team.

2) Technical/Continuous Education Program for industry technocrats ESP Heads of Productions, QA,Qc.
3) ONDLS registration of technical person.
4) Appointment of LUB's representatives as MSME in DTAB committee is in the process according constitutional provisions.

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0 में एलयूबी जोधपुर ने किया अंशदान

वन्दे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अन्तर्गत मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान–2.0 में लघु उद्योग भारती जोधपुर प्रांत, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव व विभिन्न उद्यमियों की ओर से सीएसआर मद में सत्रह लाख पचास हजार रुपये की राशि का चैक कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल को जोधपुर शहर विधायक श्री अतुल भंसाली, एलयूबी राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष श्री महावीर चौपडा, श्री प्रकाश जीरावला, जोधपुर प्रांत उपाध्यक्ष श्री दीपक माथुर की उपस्थिति में दिया गया।

J&K Delegation met CS @ Srinagar

LUB's delegation led by National Organising Secretary Shri Prakash Chandra ji met Chief Secretary of J&K Shri Atal Dulloo at Srinagar on 17th July. The delegation submitted a memorandum containing various suggestions about the enhancement of investment package registration date & amount for MSMEs which have applied for investment & have already made initial investments. The memorandum also contained many issues of local industry. On this occasion; State President Shri Praveen Pragal, Gen. Secretary Shri Agam Jain, VP Shri Ankit Gupta and Shri Fayaz Ahmed, Punjab Mass Comm. Coordinator Shri Vikrant Sharma, Shri Fahad Bhatt and Shri Tausif Mir were present.

LUB Delegation met Punjab Governor

LUB's delegation led by Shri Prakash Chandra ji met with Governor of Punjab Shri Gulab Chand Kataria at Raj Bhawan on 14th July and discussed issues of industries of Chandigarh region. Shri Kataria welcomed all members with shawls. He asked the LUB's local team to be-in-touch with him about issues related to the industry. On this occasion, National VP Shri Arvind Dhumal, State President Shri Pradeep Mongia, Media Coordinator Shri Vikrant Sharma were present.

First Ever Meeting held @ Srinagar

LUB's Srinagar Unit conducted its first meeting on 17th July. More than 30 local entrepreneurs apprised about various hurdles in the development of MSMEs in Srinagar. They were assured all assistance from LUB to resolve the problems. J&K President Shri Praveen Pargal talked about the efforts of LUB across all Indian states & UTs for the betterment of MSMEs.

Karur Unit conducts GST Awareness Program

LUB's Karur Unit of Tamil Nadu State conducted an Awareness Program for addressing the issues of MSMEs in GST. Shri. Balasubramanium and Shri. Pandiyan both Asst. Commissioners of GST Karur gave a highly commendable inputs of GST and answered queries raised by members. Jt. Gen. Secretary Shri Jeyendran gave interesting inputs on how business can thrive on becoming LUB members.

During the discussion, State EC member & Media In-charge Shri Sathyanarayanan, State Secretary Shri Narayanaswamy, State VP Shri Senthil and Unit President Shri Eashwaran were present.

Delhi State Delegation Discussed Core Issues with Industry Minister

LUB's Delhi delegation met with Delhi Industry Minister Shri Manjinder Singh Sirsa to discuss critical issues affecting the industrial areas. Shri Sirsa assured for prompt action. State President Shri Diwan Chand Gupta that his commitment underscores a proactive approach toward enhancing the sustainability and growth of Delhi's industrial sectors. On this occasion, State GS Smt. Aarti Sehgal, Past President Shri Virender Nagpal and Vice President Shri Mukesh Aggarwal along with members of the Udyog Nagar were present.

एलयूबी शिष्टमंडल ने वित्त मंत्री से जीएसटी विषयक चर्चा की

लघु उद्योग भारती शिष्टमंडल ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से संसद भवन में 24 जुलाई को भेंट की। इस विशेष भेंट में प्रमुख रूप से ग्रेनाइट एवं मार्बल पर वर्तमान में लागू 18% GST को घटाकर 5% किए जाने का अनुरोध किया गया। साथ ही, खनन विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 की रॉयल्टी पर जारी किए जा रहे GST नोटिसों को भी प्रमुखता से उठाया गया। इन दोनों विषयों पर श्रीमती सीतारमण ने गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी, एलयूबी राष्ट्रीय सचिव श्री नरेश पारीक, राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मुकेश अग्रवाल सहित श्री कपिल खुराना (उदयपुर), श्री रमन बंसल, एवं श्री रामनिवास (जालोर) भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि यह भेंट राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के विशेष प्रयासों से सुनिश्चित की गई थी क्योंकि 23 जुलाई को उद्योग भवन जयपुर में श्री राठौड़ से राजस्थान प्रदेश के मार्बल एवं ग्रेनाइट उद्योग के प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा की थी।

शिष्टमंडल ने स्टोन मार्ट आयोजन पर की चर्चा

लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान सरकार में उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव श्री आलोक गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की और 5 से 8 फरवरी, 2026 को जयपुर में आयोजित होने वाले स्टोन मार्ट एवं औद्योगिक हित के अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय सचिव श्री नरेश पारीक, पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री योगेश गौतम, राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष एवं स्टोनमार्ट के संयोजक श्री नटवरलाल अजमेरा, जयपुर अंचल के अध्यक्ष श्री महेंद्र मिश्रा एवं जोधपुर प्रांत के महासचिव श्री सुरेश कुमार विश्नोई शामिल थे।

आयुर्वेदिक योगों से नई दवाइयां बना रहा डीआरडीओ

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) आयुर्वेद के पुराने फार्मूलों को परखकर उनसे नई दवाएं बनाने की योजना पर कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में अब तक दो दवाओं के मामले में सफलता मिली है। जबकि एक दर्जन दवाओं पर शोध चल रहा है। सीएसआईआर के लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान, पालमपुर स्थित हिमालयन वनस्पति शोध केंद्र इन परंपरागत दवाओं की ट्रायल कर उनकी वैज्ञानिकता देखेंगे। इसके अलावा सीएसआईआर ने लेह में भी जड़ी–बूटियों पर शोध के लिए नए केंद्र की स्थापना की है। जबकि डीआरडीओ की लेह स्थित प्रयोगशाला इस दिशा में कार्य कर रही है। डीआरडीओ के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार उनके द्वारा विकसित सफेद दाग की दवा को एमिल फार्मास्युटिकल ने कुछ समय पूर्व बाजार में उतारा था। अब तक तीन लाख लोगों का सफलतापूर्वक उपचार किया जा चुका है। इसे डीआरडीओ ने आधुनिक साइंस की कसोटी पर भी परखा है। सीएसआईआर द्वारा विकसित मधुमेह की दवा बीजीआर 34 को बाजार में लाया जा रहा है। सीएसआईआर ने रायल्टी शेयरिंग में इस फॉर्मूले को दवा निर्माता कंपनी को सौंपा है।

सांगरिया औद्योगिक क्षेत्र में ईएसआईसी औषधालय का संचालन होगा शीघ्र

एलयूबी जोधपुर प्रांत के प्रयासों से कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा सांगरिया औद्योगिक क्षेत्र में औषधालय शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के नियोजकों एवं बीमित कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त होंगी। इस संबंध में जोधपुर प्रांत, कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा रीको के अधिकारियों ने प्रस्तावित भवन का निरीक्षण 19 जुलाई को किया। प्रांत प्रभारी श्री महावीर चोपड़ा ने बताया कि भवन को रीको से आवंटित करवाया गया है।

एमएसएमई मंत्रालय ने लघु उद्यमियों को समयबद्ध भुगतान के लिए शुरू किया पोर्टल

भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने लघु उद्यमियों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल तैयार किया है जिसका औपचारिक उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू ने किया। अब छोटे उद्योगों को देर से भुगतान से जुड़े विवादों के लिए ऑनलाइन समाधान (Online Dispute Resolution-https://odr.msme.gov.in) मिलेगा।

क्या है ODR पोर्टल ?

भारत सरकार के किसी मंत्रालय द्वारा विकसित यह पहला पूर्णतः डिजिटल विवाद समाधान पोर्टल है यह पोर्टल देरी से भुगतान की शिकायतों को दो चरणों में निपटाने की सुविधा देता है:

1- Pre-MSEFC (स्वैच्छिक प्रक्रिया):– Digital Guided Pathway& Unmanned Negotiation
दोनों पक्षों की सहमति से बिना कोर्ट के बाहर समझौते की कोशिश।

2- MSEFC (कानूनी प्रक्रिया): Conciliation @ Mediation, Arbitration
यह MSMED Act, 2006 के तहत बाध्यकारी है।

पोर्टल की खासियतः पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन – e-filing, Hearing Scheduling, Case Tracking और पेपरलेस, पारदर्शी एवं त्वरित है।

आगरा में विद्युत दरों के संबंध में एलयूबी ने रखा उद्यमियों का पक्ष

लघु उद्योग भारती आगरा के जिला अध्यक्ष श्री विजय गुप्ता ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष आयोजित

जनसुनवाई में औद्योगिक विद्युत दरों में प्रस्तावित वृद्धि का विरोध किया। उन्होंने आयोग के समक्ष तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश में विद्युत दरें पहले से ही पड़ोसी राज्यों–मध्यप्रदेश, राजस्थान व उत्तराखंड की तुलना में अधिक हैं। ऐसे में दरों में और वृद्धि होने से उद्योगों की उत्पादन लागत और प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे निवेश हतोत्साहित होगा और उद्योग पलायन की स्थिति बन सकती है।

श्री गुप्ता ने सुझाव दिया कि–

- दो वर्षों के अनिवार्य विद्युत आपूर्ति गारंटी अनुबंध (गारंटी एग्रीमेंट) की अवधि को घटाकर छह माह किया जाए, या समाप्त किया जाए ताकि नवाचार कर रहे नए उद्योग बिना लंबी बाध्यता के प्रयोग कर सकें।
- समय पर भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को क्रेडिट स्कोर रेटिंग के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाए तथा उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएं।

हरियाणा में विशेष बैठक आयोजित

लघु उद्योग भारती की विशेष बैठक का आयोजन हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में 14 जुलाई को किया गया। संगठन के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी ने भारतीय उद्योगों की तीव्र गति से हो रही प्रगति में लघु उद्योग भारती की सहभागिता और स्वावलंबी भारत अभियान की सार्थकता पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर स्वावलंबी भारत अभियान व स्वदेशी जागरण मंच के आईटी प्रमुख श्री राधेश्याम चोयल द्वारा तैयार किये गए पोर्टल माईएसबीए

(mysba.co.in) का बटन दबाकर लॉन्च किया। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष श्री शुभ आदेश मित्तल ने आगामी दो वर्षों के लिए करनाल इकाई की नव कार्यकारिणी की घोषणा की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अरविंद धूमल सहित बड़ी संख्या में उद्यमीगण उपस्थित रहे।

जोधपुर में पर्यावरण जटिलताओं के समाधान पर हुई चर्चा

एलयूबी जोधपुर प्रांत और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के संयुक्त तत्वावधान में उद्यमी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें उद्योगों में पर्यावरणीय अनुमति संबंधी जटिलताओं के व्यावहारिक समाधान पर चर्चा की गई। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा ने कहा कि उद्योग आज के दौर में तकनीक, उत्पादन और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाकर काम कर रहे हैं। उन्होंने उद्योग संचालन की प्रक्रिया के सरलीकरण पर जोर दिया। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष श्री रवि कुमार सुरपुर, एलयूबी प्रदेश उपाध्यक्ष श्री महावीर चोपड़ा, प्रांत महामंत्री श्री सुरेश कुमार विश्नोई, क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती कामिनी सोनगरा भी उपस्थित रहीं।

मुरादाबाद इकाई ने की थर्ड पार्टी निरीक्षण प्रक्रिया को सरल करने की मांग

एलयूबी उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद इकाई ने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन श्री आर.पी. सिंह से भेंट की और थर्ड पार्टी निरीक्षण की प्रक्रिया को सरल करने का आग्रह किया। इकाई अध्यक्ष श्री अंशुल अग्रवाल ने बताया कि थर्ड पार्टी निरीक्षण में जब किसी निर्यात इकाई में कोई कमी इंगित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, बहुत कम समय होने के कारण उद्यमी उसका जवाब समय से देने में असमर्थ होते हैं।

हाथरस में उद्योग समन्वय बैठक आयोजित

लघु उद्योग भारती के संयुक्त राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष श्री राकेश गर्ग ने हाथरस में वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहभागिता की एवं कलेक्ट्रेट सभागार में उद्योग समन्वय बैठक में उद्योगों से सम्बद्ध कार्यों को प्राथमिकता से करने के लिए निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर, स्थानीय सांसद एवं विधायक तथा औद्योगिक विकास से जुड़े अधिकारी उपस्थित रहे।

कोटा के संयुक्तप्रतिनिधिमंडल ने उद्योग सचिव को प्रस्तुत किया ज्ञापन

लघु उद्योग भारती कोटा की समस्त इकाइयों एवं दी एसएसआई एसोसिएशन के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर में उद्योग सचिव श्री आलोक गुप्ता को उद्योगों से संबंधित विभिन्न समस्याओं का ज्ञापन प्रस्तुत किया। ज्ञापन में निम्नलिखित प्रमुख मुद्दे रखे गए–

- रीको से संबद्ध विभिन्न समस्याएं– ट्रांसफर एरिया, पर्यावरण एरिया, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट एरिया में ट्रांसफर की जटिलता
- पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अनुमतियों (छब्ब) की जटिल प्रक्रिया
- जीएसटी में आ रही व्यावहारिक परेशानियां
- फायर एनओसी जारी कराने में आने वाली अड़चन
- नगरीय विकास कर से संबंधित समस्याएं
- सोलर प्लांट लगाने में तकनीकी और प्रशासनिक जटिलताएं
- औद्योगिक क्षेत्रों में माफिया का बढ़ता हस्तक्षेप
- इनकम टैक्स में सब्सिडी की टैक्स एबिलिटी से उद्योगों पर अतिरिक्त बोझ

प्रतिनिधिमंडल में विधायक श्री संदीप शर्मा, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय सलाहकार श्री गोविन्दराम मित्तल, कोटा वृहद इकाई अध्यक्ष श्री अंकुर गुप्ता, कोटा उत्तर इकाई अध्यक्ष श्री संजय शर्मा, एसएसआई एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मनोज राठी, सचिव श्री आशुतोष जैन एवं वरिष्ठ सदस्य श्री राजेन्द्र उपस्थित रहे।

पंजाब में साइबर सुरक्षा पर विशेष सत्र

एलयूबी पंजाब महिला इकाई की ओर से साइबर सुरक्षा से जुड़े खतरों और उनके व्यावहारिक समाधान के बारे में आयोजित विशेष सत्र में श्रीमती ईशा ठाकुर ने जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रदीप मोंगिया, महासचिव श्री विवेक राठौड़, जालंधर इकाई अध्यक्ष श्री अनिरुद्ध एवं सचिव श्री वरुण भल्ला सहित उद्यमीगण उपस्थित रहे।

पंजाब प्रदेश की बैठक में हुआ उद्योग हितैषी चिंतन

लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय संगठन महामंत्री श्री

प्रकाश चन्द्र जी ने पंजाब प्रवास के दौरान प्रदेश की कोर कमेटी को उद्योग हितैषी नीतियों के क्रियान्वयन, प्रदेश व केंद्र सरकार की भूमिका एवं जीएसटी सहित विविध विषयों पर मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय उपाध्यक्ष एडवोकेट श्री अरविंद धूमल, उत्तरी क्षेत्र के सदस्यता अभियान समन्वयक श्री विक्रान्त शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रदीप मोंगिया, संयुक्त महासचिव श्री अनिल शर्मा, होशियारपुर के पूर्व अध्यक्ष श्री अमित गोयल, महासचिव श्री हरपिंदर सिंह गिल उपस्थित रहे।

हिमाचल प्रदेश कार्यकारिणी का हुआ पुनर्गठन

एलयूबी हिमाचल प्रदेश कार्यकारिणी का पुनर्गठन राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अरविन्द धूमल और राष्ट्रीय सचिव श्री विक्रम बिंदल की उपस्थिति में 15 जुलाई को बद्दी में किया गया। नई कार्यकारिणी में संरक्षक श्री हरबंस पटियाल, श्री एमपी शर्मा, अध्यक्ष श्री अखिल मोहन अग्रवाल, सचिव श्री अश्वनी गर्ग, कोषाध्यक्ष श्री अजय चौहान, उपाध्यक्ष श्री संजीव शर्मा, श्री प्रकाश वर्मा, श्री विनोद खन्ना, श्री पंकज मित्तल, संयुक्त सचिव श्री नवीन रावत, श्री प्रमोद कुमार, श्री नीरज गुप्ता, मीडिया कोऑर्डिनेटर श्री विकास सेठ, कानूनी सलाहकार एडवोकेट श्री नवरतन देव शर्मा, आईटी विंग प्रभारी श्री पीयूष शर्मा एवं कार्यकारिणी सदस्यों में श्री बलराम अग्रवाल, श्री संजीव वर्मा, श्री अरुण शर्मा, श्री सतनाम सिंह को मनोनीत किया।

भीलवाड़ा में स्वयंसिद्धा-2025 प्रदर्शनी आयोजित

एलयूबी राजस्थान की भीलवाडा इकाई ने स्वयंसिद्धा–2025 का आयोजन 1 एवं 2 जुलाई को किया। प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी, जिला कलेक्टर श्री जसमीत

संधू और पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र प्रधान ने विविध उत्पादों को प्रदर्शित करने वाली महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया।

महिला इकाई अध्यक्ष श्रीमती पल्लवी लढा ने बताया कि महिला सशक्तिकरण एवं स्वदेशी विषयक सेमिनार में उपमुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा, लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा और मुख्य वक्ता डीआरडीओ की वैज्ञानिक डॉ. मीना मिश्रा ने महिला उद्यमिता पर विचार रखे। कार्यक्रम में स्वयंसिद्धा आयाम प्रमुख श्रीमती अंजू सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती रीना राठौड़ सहित चित्तौड़गढ़ और उदयपुर महिला इकाई सदस्य एवं उद्यमी गण उपस्थित रहे। कार्यशाला में इको फ्रेंडली गणेश जी और रेजिन राखी को बनाना सिखाया।

राजस्थान में वैध खनन को किया प्रोत्साहित

राजस्थान में वैध खनन को बढावा देने और खजिन क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग पर जोर देते हुए क्वारी लाईसेंस एवं अप्रधान खनिज लीज धारको को राहत प्रदान की गई। जोधपुर प्रांत प्रभारी श्री महावीर चौपडा ने बताया कि क्वारी लाईसेंस एवं अप्रधान खनिज लीज धारकों को खनन पट्टों की अवधि वृद्धि के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 30 सितम्बर तक बढ़ा दी गयी है। इसके लिये राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 9 (3 ए) एवं नियम 10 (3 ए) में संशोधन किया गया है। साथ ही अप्रधान खनिज लीज अवधि में वृद्धि के अधिकार संबंधित खनिज अभियन्ता व सहायक अभियन्ता को दिये गये हैं। इसी तरह अप्रधान खनिज के खनन पट्टों और क्वारी लइसेंस की अवधि वर्ष 2040 तक बढाई गयी है। इसकी प्रीमियम राशि अधिकतम पांच किस्तों

मे जमा कराने की भी छूट दी गयी है। इस हेतु संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट की थी।

आयुर्वेद इकाई शिष्टमंडल ने आयुष मंत्री से की भेंट

लघु उद्योग भारती की आयुर्वेद इकाई के शिष्टमंडल ने 18 जुलाई को उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचन्द बैरवा से भेंट कर आयुर्वेदिक औषधि निर्माताओं की समस्याओं से अवगत कराया। इस अवसर पर अनुभवी स्टेट लाइसेंसिंग अधॉरिटी की नियुक्ति, विभाग में कार्यों की समय सीमा निक्षित करने, नए उत्पादों के अनुमोदन व अनुज्ञा–पत्र व जीएमपी के नवीनीकरण की ऑनलाइन ट्रेकिंग, आरजीएचएस योजना में राजस्थान प्रांत के संपूर्ण जीएमपी धारकों की सहभागिता में पारदर्शिता, सरकारी खरीद में लघु आयुर्वेद औषधि निर्माताओं को टर्नओवर व टेस्टिंग इत्यादि नियमों में छूट, शास्त्रोक्त आयुर्वेद औषधियों को अन्य डोसेज फॉर्म में अनुमोदन नहीं दिया जाना, औषधि निर्माता को औषधि प्रचार हेतु UIN जारी करने एवं आयुर्वेदिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने जैसे महत्वपूर्ण विषय रखे। शिष्टमंडल में प्रदेश महामंत्री श्री सुधीर कुमार गर्ग, जयपुर संभाग अध्यक्ष श्री महेन्द्र मिश्रा, आयुर्वेद इकाई संयोजक श्री विकास योगीराज, सहसंयोजक श्री अनिरुद्ध गोस्वामी, श्री पवन शर्मा व श्री उदिगण गुप्ता शामिल थे।

जगतपुरा इकाई ने स्वयंसिद्धा प्रदर्शनी की आयोजित

एलयूबी जयपुर अंचल की जगतपुरा महिला इकाई ने स्वयंसिद्धा राखी एवं तीज प्रदर्शनी 19–20 जुलाई को आयोजित की। इकाई अध्यक्ष श्रीमती वैशाली वशिष्ठ ने बताया कि One Stall One Skilled Child के विचार के साथ आयोजित इस प्रदर्शनी में 55 स्टॉल्स पर महिलाओं ने आकर्षक हस्तनिर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया। इस अवसर

पर जयपुर शहर की महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर, अक्षय पात्र मंदिर समिति के उपाध्यक्ष श्री राधा प्रिय प्रभु और श्री सिद्धस्वरूप दास, यूनियन बैंक की ब्रांच मैनेजर श्रीमती ज्योत्सना, डीआईसी की मुख्य प्रबंधक श्रीमती शिल्पी पुरोहित, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री ताराचंद गोयल, प्रदेश महासचिव श्री सुधीर गर्ग, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू सिंह, एवं प्रान्त कोषाध्यक्ष श्री उदय भुवालका सहित उद्यमीगण उपस्थित रहे।

बिहार में उद्यमी सम्मान समारोह आयोजित

एलयूबी बिहार प्रदेश इकाई ने उद्यमी सम्मान समारोह अखिल भारतीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी, उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा, पूर्व अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री ओ.पी. मित्तल तथा श्री सुरेश रुंगटा की उपस्थिति में 24 जुलाई को पटना में आयोजित किया। पहले सत्र में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में संगठन की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई।

दूसरे सत्र में आयोजित उद्यमी सम्मेलन में बिहार के विभिन्न जिलों से लगभग 350 उद्यमियों ने भाग लिया। सम्मेलन में प्रांत अध्यक्ष श्री श्याम सुन्दर भीमसरिया ने लघु एवं मध्यम उद्योगों के समक्ष आ रही समस्याओं, विशेष रूप से BIADA से जुड़ी चुनौतियों को प्रमुखता से उठाया। उद्यमियों ने अपने अनुभव साझा किए और राज्य सरकार से सहयोग की अपेक्षा जताई। उद्योग मंत्री श्री नितीश मिश्रा ने उद्यमियों को

आश्वस्त किया कि सरकार लघु उद्योगों के लिए अनुकूल नीतियां बनाएगी और हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। कार्यक्रम के अंतिम सत्र में बिहार के प्रेरणादायक उद्यमियों को "उद्यमिता सम्मान 2025" से सम्मानित किया गया।

एलयूबी शिष्टमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय सचिव से की यूटी उद्योगों पर चर्चा

लघु उद्योग भारती के शीर्ष प्रतिनिधिमंडल ने अखिल भारतीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी और महासचिव श्री ओम प्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव श्री गोविंद मोहन से 23 जुलाई को नई दिल्ली में भेंट की। इस बैठक में केंद्र शासित प्रदेशों के एमएसएमई सेक्टर के समक्ष उभर रही चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा की गई।

प्रतिनिधिमंडल ने यूटीज में व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने हेतु नीतियों की समीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अत्यधिक लीज किराए, उच्च बिजली दरें, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचें से सम्बधित परियोजनाओं में देरी, तटीय क्षेत्र नियमन (CRZ) योजनाओं के लंबित होने तथा नई औद्योगिक नीति की समीक्षा की मांग की गई। साथ ही, लीज अवधि को 30 वर्ष से बढ़ाकर 99 वर्ष करने की सिफारिश की गई।

चंडीगढ़ के लिए, भवन नियमों में लचीलापन लाने, लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सरलता, खाली औद्योगिक प्लॉट्स के उपयोग हेतु नीति और ऑटोमोबाइल क्षेत्र को सामान्य उद्योग के रूप में मान्यता दिए जाने की मांग की गई।

पुडुचेरी के संबंध में, प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा गलियारों में शामिल किए जाने, जीएसटी पंजीकरण सीमा को रू20 लाख से बढ़ाकर रू40 लाख करने, समय पर सब्सिडी जारी करने, केंद्रीकृत लाइसेंसिंग व्यवस्था और एमएसएमई विकास सुविधा कार्यालय (MSME DFO) की स्थापना की सिफारिश की। साथ ही, भुगतान में देरी के कारण एनपीए (गैर–निष्पादित परिसंपत्ति) की समस्या को दूर करने के लिए प्रणालीगत सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसी के साथ एम्प्ल्योयमेंट लिंक्ड इंसेटिव (ईएलआई) योजना की जानकारी एवं विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर जम्मू–कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी सहित विभिन्न यूटीज के उद्यमीगण भी उपस्थित थे।

लघु उद्योग भारती के प्रयासों से कच्चे आढ़तियों को मिला नया पहचान कोड

लघु उद्योग भारती का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल, अखिल भारतीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से कच्चे आढ़तियों की कर संबंधी समस्याओं के बारे में इसी वर्ष मई में भेंट की थी। चर्चा में ITR फॉर्म में उनके लिए अलग व्यवसाय कोड की मांग रखी गई थी, उसे पूरा कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2024–25 की ITR यूटिलिटी में एक नया कोड–09029–कमीशन एजेंट्स (कच्चा आढ़तिया) शामिल किया गया है। अब सभी कच्चे आढ़त व्यापारी सही कोड का चयन कर अपनी आयकर रिटर्न (ITR) को भर सकेंगे, ताकि उनकी व्यावसायिक पहचान सही रूप से दर्शाई जा सके।

हरियाणा शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री से की उद्योगों पर चर्चा

एलयूबी हरियाणा शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से चंडीगढ़ में प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर के उद्योगों से जुड़ी मांगों को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया किया कि नॉन कन्फर्मिंग एरियाज वाले विषय की घोषणा बजट में भी की थी, उसे जल्द ही पोर्टल पर लॉन्च किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष श्री शुभ आदेश मित्तल, श्री रमन सलूजा, श्री सुधीर चंद्रा, श्री संजय डाटा, श्री विनोद बंसल एवं श्री सुभाष चंद उपस्थित थे।

जयपुर के सीएसआईआर-सीरी कैंपस में उद्यमियों ने उन्नत तकनीकों को जाना

एलयूबी जयपुर अंचल के 33 उद्यमियों के दल ने सीएसआईआर–सीरी (सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट), का 11 जुलाई को कैंपस विजिट कर उन्नत तकनीकों एवं अत्याधुनिक मशीनों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अंचल अध्यक्ष श्री महेंद्र मिश्रा ने बताया कि वैज्ञानिकों ने नवीनतम शोध और तकनीकी नवाचारों को साझा कर सभी सदस्यों को उद्योग क्षेत्र में तकनीकी उन्नति की दिशा में प्रेरित किया।

गोधरा इकाई ने एआई तकनीक पर किया सेमिनार

एलयूबी गुजरात की गोधरा इकाई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 21 जुलाई को सेमिनार आयोजित किया। सेमिनार में एआई सेंटर फॉर एक्सीलेंस गांधीनगर से फैकल्टी श्री सिद्धार्थ कामत ने बताया कि एआई उद्योग में कैसे मदद कर सकता है। इस अवसर पर लघु उद्योग भारती के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलदेव भाई प्रजापति, राष्ट्रीय मंत्री श्री श्याम सलूजा, प्रदेश अध्यक्ष श्री ईश्वर भाई पटेल और उद्यमीगण उपस्थित रहे।

संगठन प्रयासों से दिल्ली फैक्टरी लाइसेंस में मिली बड़ी सफलता

एलयूबी दिल्ली प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग के लिये किए गए प्रयासों में बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली नगर निगम ने 52 औद्योगिक क्षेत्रों से MCD फैक्ट्री लाइसेंस को समाप्त कर प्रोपर्टी टैक्स पोर्टल पर जमा लाइसेंस फीस रसीद (फैक्टरी के वार्षिक प्रोपर्टी टैक्स का 5%) को एमसीडी फैक्टरी लाइसेंस के रूप में मान्यता देने पर सैद्धान्तिक रूप से सहमति दे दी है। दिल्ली प्रदेश इकाई ने इसके लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सचदेवा, महापौर सरदार राजा इकबाल, नेता सदन श्री प्रवेश वाही, स्थाई समिति अध्यक्ष श्रीमती सत्या शर्मा एवम निगम आयुक्त श्री अश्वनी कुमार से इस बारे में अनुरोध किया था।

समालखा (हरियाणा) में उद्यमी सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर

हरियाणा के समालखा में 13 से 15 सितंबर को लघु उद्योग भारती की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक एवं उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए 17 जुलाई को संगठन के विशेष दल ने पानीपत जिले के समालखा खंड के पट्टी कल्याणा गांव में श्री माधव जन सेवा न्यास (ट्रस्ट) द्वारा संचालित सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र का दौरा किया।

राष्ट्रीय महासचिव श्री ओमप्रकाश गुप्ता की अगुवाई में हरियाणा एवं दिल्ली प्रदेश के शीर्ष पदाधिकारियों ने भवन की समस्त सुविधाओं का अवलोकन किया और आवश्यक प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा की।

इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव श्री नरेश पारीक एवं श्रीमती अंजू बजाज, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष श्री जनक भाटिया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री अरुण बजाज, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष श्री दीवान चंद्र गुप्ता, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष श्री शुभादेश मित्तल के साथ दोनों प्रदेशों की टीम के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे।

इस कार्यक्रम में एग्जिबिशन भी आयोजित होगी जिसमें केंद्र, राज्य सरकारों के साथ उद्यमीगण अपने प्रोडक्ट और सर्विसेस को शोकेस करेंगे। लघु उद्योग भारती विशेषांक उद्योग उत्थान भी प्रकाशित किया जाएगा।

देवास में एमएसएमई कार्यशाला आयोजित

लघु उद्योग भारती मध्यप्रदेश, एमएसएमई विभाग, एवं लघु उद्योग निगम द्वारा के संयुक्त तत्वावधान में देवास में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजित की गई। देवास इकाई अध्यक्ष श्री सुभाष शिंदे ने बताया कि लीन प्रबंधन, ज़ेड प्रमाणन, बौद्धिक संपदा अधिकार एवं जेम पोर्टल पर विशेषज्ञों ने जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर एलयूबी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री समीर मूंदड़ा, जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र की प्रबंधक श्रीमती सपना उमट सहित उद्यमी गण उपस्थित रहे।

बालोतरा इकाई ने की रेल राज्य मंत्री से भेंट

नई दिल्ली में भारत सरकार के रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह से मुलाकात कर बालोतरा, बाड़मेर से बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई एवं अहमदाबाद के लिए नई रेल चलाने की मांग की। एलयूबी राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री शांतिलाल बालड़ ने बताया कि बालोतरा रेलवे स्टेशन पर रेल सुविधाओं का विस्तार करने एवं वाशिंग सेंटर की मांग की गई। बाड़मेर–यशवंतपुर एक्सप्रेस ट्रेन के फेरे बढ़ाने एवं पारलू स्टेशन पर ठहराव करने के साथ रिफाइनरी को बालोतरा रेलवे स्टेशन से जोड़कर पुनः जंक्शन के रूप में विकसित करने की मांग की गई।

जयपुर सेंट्रल ने आयोजित की स्वयंसिद्धा प्रदर्शनी

एलयूबी सेन्ट्रल महिला इकाई ने स्वयंसिद्धा प्रदर्शनी का आयोजन 11 जुलाई को किया। ग्रेटर जयपुर महापौर श्रीमती सौम्या गुर्जर ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर महिला उद्यमियों को सराहा। इकाई अध्यक्ष श्रीमती रमा अग्रवाल ने बताया कि प्रदर्शनी में 47 स्टॉल पर हस्तनिर्मित एवं घरेलू उत्पादों का अनूठा संग्रह प्रस्तुत किया गया। प्रदर्शनी में प्रमुख आकर्षण 51 प्रकार के मिलेटस प्रोडक्ट भी रहे।

LUB's Tamilnadu State Unit Released THOLIL SUDOROLI Quarterly Magazine in presence of National Jt. GS M. Mohanasundaram, National VP Shri Hariharan & State President Dr. VSV Chezhian.

Dy. CM Rajasthan Smt. Diya Kumari Inaugurated a Two Day Swayamsiddha Exhibition organised by LUB's Vidyadhar Nagar Women Unit at Jaipur on 26th July, 2025.

LUB's Delegation led by National Secretary Shri Naresh Pareek accompanied State VP Shri Mukesh Agarwal & other Officials met Industry Minister Shri Rajyavardhan Singh Rathore for GST Issues at Jaipur on 22nd July, 2025.

LUB's Goa Unit & 23:23 Designs, in collaboration with GSRLM, successfully conducted a Workshop on Packaging & Labelling for MSEs and SHGs at Panjim on 25th July, 2025.

LUB's Bengal Delegation met Joint Director, MSME -DFOTC, Kolkata Shri Pradip Kumar Das for MSMEs Issues. VP Paschim Bango Shri Rajesh Mishra & Jt. Secretary Shri Arun Soni, President Dakshin Bango Shri Vijay Agarwal & Sr. VP Shri Batteswar Jha were present on 18th July, 2025.

LUB's Visakhapatnam Unit & ESIC jointly hosted an Awareness Session on SPREE 2025 at Auto Nagar on 26th July, 2025.

LUB's Kala Amb Unit (HP) was reoragnied in the presence of National Org. Secretary Shri Prakash Chandra ji, National VP Shri Arvind Dhumal, National Secretary Shri Vikram Bindal, State President Shri Harbans Patial & Treasurer Shri Akhil Mohan Agarwal on 15th July, 2025.

New Executive of Panchkula District was announced in the presence of National Org. Secretary Shri Prakash Chandra Ji, National VP Shri Arvind Dhumal, Haryana State President Shri Shubh Adesh Mittal, Punjab President Shri Pardeep Mongia, NWC Member Shri Ramakant Bharadwaj on 15th July, 2025.

Rajasthan Industry Minister Shri Rajyavardhan Singh discussed core issues with Entrepreneurs in the presence of LUB's National President Shri Ghanshyam Ojha, Rajya Sabha MP Shri Rajendra Gehlot & President MCCI Shri Prasanna Chand Mehta at Jodhpur on 11th July, 2025.

IIM Jammu & LUB's J&K Unit conducted an Inspiring Orientation for MBA Program focused on Cultivating a Future-ready, Entrepreneurial Mindset. State President Shri Parveen Pargal and GS Shri Aagam Jain participated as Panellists on 16th July, 2025.

LUB' Jodhpur Prant & Central Arid Zone Research Institute jointly conducted a 10 Day Training Program on Millet Products. On the completion, 16 Attendees received Certificates in the presence of CAZRI Director Dr. Sumant Vyas, LUB's National President Shri Ghanshyam Ojha, Coordinator Smt. Manju Saraswat & Prant Prabhari Shri Mahavir Chopra on 24th July, 2025.

LUB's Telangana State AGM held in the esteemed presence of National Org. Secretary Shri Prakash Chandra ji. A New Team was formed with the President Shri Vasanatham Venkateswarlu, General Secretary Shri K. Narendranath Dutt & Treasurer Shri Anuj Khandelwal at Hyderabad on 17th July, 2025.

LUB's New Sunam Unit of Sangrur District (Punjab) was announced in presence of National Org. Secretary Shri Prakash Chandra Ji, National VP Shri Arvind Dhumal & Punjab President Shri Pardeep Mongia on 13th July, 2025

LUB's Former National President Shri OP Mittal & President North Bengal CA Aditya Mitruka met Union Minister for Education Shri Dharmendra Pradhan and Discussed Entrepreneurship amongst the Youth at New Delhi.

LUB's Team led by National General Secretary Shri O.P Gupta had a productive meeting with Secretary-MSDE Shri Rajit Punhani. National Secretary Smt. Anju Bajaj and National Coordinator Net Zero Aayam Smt. Jayanti Goela were also present at New Delhi on 10th July, 2025.

LUB's Kashi Prant (UP) & MSME DFO jointly conducted a Special Session on Entrepreneurship in presence of Prant President Shri Rajesh Singh on 15th July, 2025.

LUB's Neemrana Unit of Rajasthan conducted an Important Meeting for 3 Day India Industrial Fair (IIF)-2025 to be held at Bhiwadi on 19-21 Sept., 2025.

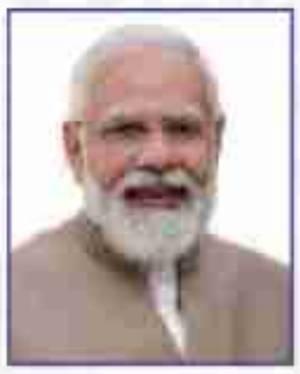

Shri Narendra Modi
Hon'ble Prime Minister
Bharat

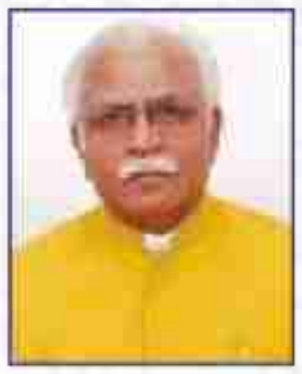

Shri Manohar Lal Khattar
Hon'ble Union Minister Power,
Housing & Urban Affairs

Smt. Shobha Karandlaje
Hon'ble Union MoS
MSME, Labour & Employment

Shri Nayab Singh Saini
Hon'ble Chief Minister
Haryana

INDUSTRY INVITE

for

UDYAMI SAMMELAN

&

EXHIBITION FOR INDUSTRY PRODUCTS

Organized by:

लघु उद्योग भारती

LAGHU UDYOG BHARATI

32Years for Excellence in Protection & Promotion forMSMEs

Theme:

EMPOWERED MSMEs FOR VIKSIT BHARAT

13 - 14 - 15 Sept.,2025

Venue : Sewa Sadhana & Gram Vikas Kendra

Run by Shri Madhav Jan Sewa Nyas, Patti Kalyana
Samalkha Block, Distt. Panipat, Haryana

Principal Sponsor

HSIIDC

Supported by:

MSME

GeM Government e Marketplace

sidbi

MAKE IN INDIA

STAND UP India
Endeavour and Prosper

राजस्थान सरकार

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

मुख्यमंत्री
वृक्षारोपण
महा अभियान
2025

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

हरियालो राजस्थान

हर घर लगे एक पेड़ माँ के सम्मान में, प्रकृति के नाम

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान से प्रेरित, राजस्थान सरकार का हरित भविष्य की ओर मजबूत कदम

10 करोड़ पौधों का रोपण एवं संरक्षण।

70,000 हेक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण।

माँ के नाम एक वृक्ष,
जीवन के नाम एक संकल्प।

नर्सरी देखने और पौधा खरीदने के लिए QR कोड को स्कैन करें

#एक_पेड़_माँ_के_नाम

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

राजस्थान संवाद

UDYOG TIMES

UDYOG TIMES
OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI
30 July - 2025
Registration No. RAJBIL/2016/69093
Postal Reg. No. : Jaipur City/433/2020-22

Follow us

X lubindia
YouTube @lubBharat
LinkedIn laghu-udyog-bharati
Facebook lubindia
Instagram lub.india

LUB's Monthly Magazine Published by OP Mittal Printed at Raj Blocks, 22 Godown Ind. Area Kartapura, JAIPUR-302019